He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड ३ --- उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं॰ 44] No. 44] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 1998/माघ 22, 1919 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 1998/MAGHA 22, 1919

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता बिभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1998

सा.का.नि. 75(अ).— केन्द्रीय सरकार, बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियिम, 1984 (1984 का 51) की धारा 109 द्वारा प्रदक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकर, संपत्ति और निधियां,लेखा, लेखा-परीक्षा, परिसमापन तथा डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निष्नालिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, संपत्ति और निधियां, लेखा, लेखा-परीक्षा परिसमापन तथा डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन) (संशोधन) नियम, 1998 होगा ।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, संपत्ति और निधियां, लेखा, लेखा-परीक्षा, परिसमापन तथा डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन) नियम, 1985 के नियम 8 में वित्तीय उपबन्ध के पश्चात् निम्मलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

''बशर्ते यह भी कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी सहकारी बैंक का निदेशक मण्डल ऐसे अप्राप्त और डूबे हुए ऋणों के पच्चीस प्रतिशत तक रद्द कर सकेगा और ये डूबे हुए ऋण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे अर्थात् :—

- (क) अप्राप्त और दूबे हुए ऋणों का रद्दीकरण ऐसे ऋणों के मामलों में ही किया जाएगा जिन्हें लेखा-परीक्षक द्वारा दूबे हुए ऋण प्रमाणित कर दिया गया है,
- (ख) इबे हुए ऋणों का रद्दीकरण बैंको के विशृद्ध लाभ से इस प्रयोजनार्थ सुजित अप्राप्त एवं इबी हुई ऋण निधि में से ही अनुमत्य होगा।
- (ग) एक वर्ष में इबे ऋण के रूप में रद्द की गई कुल राशि अग्राप्य और इबी ऋण निधि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।''

[सं. एल-11012/9/97-एल. एंड एम.]

पाल जोसेफ, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: --मूल नियम भारत के राजपत्र के सं., सा.का.नि. 812 (ई) तारीख 28 अक्तूबर, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे।

415 GI/98

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 1998

G.S.R. 75(E).— In exercise of the powers conferred by section 109 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Multi-State Cooperative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985 namely:—

- (1) These rules may be called the Multi-State Cooperative Scoeities (Privileges, Properties and Funds, Accounts Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) (Amendment) Rules, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Multi-State Cooperative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985, in rule 8, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the Board of Directors of a Cooperative Bank registered under the Act may write off bad debts not exceeding twenty five per cent of the irrecoverable and bad debts subject to the following conditions namely:—

- (a) the writing off the irrecoverable and bad debts shall be only in respect of debts which have been certified as bad debts by the auditor;
- (b) the writing off of the bad debts shall be permitted only against Irrecoverable and Bad Debt Fund created for this purpose from out of the net profits of the Bank;
- (c) the total amount written off in a year as bad debts shall not exceed twenty five per cent of the Irrecoverable and Bad Debt Fund".

[No. L-11012/9/97-L&M]

PAUL JOSEPH, Jt Secy.

Note: -The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 812(E) dated 28th October, 1985.